

उत्तर प्रदेश में भारत के पहले उन्नत विनिर्माण केंद्र के लिए महत्वपूर्ण सार्वजनिक-निजी कार्यशाला का आयोजन

- उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर भारत के पहले उन्नत विनिर्माण केंद्र की स्थापना पर की चर्चा
- मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने वैश्विक विनिर्माण में उत्तर प्रदेश की रणनीतिक भूमिका को रेखांकित किया तथा राज्य में सार्वजनिक-निजी उन्नत मैन्युफैक्चरिंग केंद्र की स्थापना हेतु सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की
- हितधारकों ने भारत में उन्नत विनिर्माण के भविष्य पर विचार-विमर्श किया

लखनऊ, 10 अगस्त 2024 – उत्तर प्रदेश सरकार और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के सहयोग से "भारत उन्नत विनिर्माण केंद्र पर सार्वजनिक-निजी कार्यशाला" का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला पिकअप भवन, लखनऊ में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में भारत के पहले उन्नत विनिर्माण केंद्र की स्थापना की नींव रखना था।

यह केंद्र अत्याधुनिक तकनीकों, डिजिटलीकरण, और नवाचार के लिए एक हब के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। यह पहल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक स्वतंत्र राष्ट्रीय और थीमेटिक केंद्रों के नेटवर्क में शामिल होगी, जिनमें चौथी औद्योगिक क्रांति (C4IR) के केंद्र भी शामिल हैं। ये केंद्र समावेशी तकनीकी शासन को बढ़ावा देने और बहु-हितधारक संवाद और सहयोग के माध्यम से जिम्मेदार डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने इस सत्र की अध्यक्षता की। कार्यशाला का शुभारंभ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाय चैन के ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजी हेड, श्री कायराकोस त्रिअंटफिलिडिस द्वारा स्वागत भाषण से हुआ। अपने संबोधन में, श्री सिंह ने भारत के औद्योगिक क्षेत्र के भविष्य में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया, जिसमें राज्य की मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र, सहायक नीति वातावरण, और गतिशील उद्यमशीलता की भावना पर जोर दिया गया।

श्री मनोज कुमार सिंह जी ने उत्तर प्रदेश को उन्नत विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि यह पहल उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में बदलने के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के साथ मेल खाती है। श्री सिंह ने राज्य की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को 25% से बढ़ाकर 45% करने और उत्तर प्रदेश को देश के उन्नत विनिर्माण परिदृश्य में अग्रणी बनाने के लक्ष्य पर प्रकाश डाला।

इसके बाद, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन (C4IR) नेटवर्क की एशिया की एंगेजमेंट लीड और पार्टनर एंगेजमेंट की प्रमुख, श्रीमती वंदना मेनन ने उन्नत विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला के लिए वैश्विक केंद्र का अवलोकन प्रस्तुत किया। इसके बाद, श्री कायराकोस त्रिअंटफिलिडिस ने भारत उन्नत विनिर्माण केंद्र की अवधारणा, इसके प्रमुख फोकस क्षेत्रों और केंद्र की चार प्रमुख प्राथमिकताओं: लचीली मूल्य श्रृंखलाएं, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मानव-केंद्रित परिवर्तन और सतत प्रणाली पर एक प्रस्तुति दी।

कार्यशाला में पीटीसी इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, आदित्य बिड़ला ग्रुप, हायर, जेके सीमेंट, अशोक लीलैंड, ग्रीनलैम, हुंडई इंडिया, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आदित्य बिड़ला ग्रुप, आरएसीएल ग्रीनटेक लिमिटेड, भारतीयम बेवरेजेज सहित 40 से अधिक प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्होंने प्रस्तावित उन्नत विनिर्माण केंद्र की रणनीतिक दिशा पर गहन चर्चा की। हितधारकों ने इस पर विचार किया कि यह केंद्र वैश्विक और स्थानीय एजेंडा को कैसे जोड़ सकता है और वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश की स्थानीय क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकता है। केंद्र के भारत में प्रासंगिक वैश्विक पहलों का नेतृत्व करने और वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय सार्वजनिक-निजी हितधारकों के अद्वितीय नेटवर्क को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

कार्यशाला के दौरान, प्रतिभागियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश प्रक्रियाओं और समग्र व्यावसायिक वातावरण को बेहतर बनाने के तरीके पर विचार-विमर्श किया। यह खुला मंच विशेष रूप से मूल्यवान साबित हुआ, जिससे हितधारकों को अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने और राज्य में उन्नत विनिर्माण के भविष्य को आकार देने में योगदान करने का अवसर मिला।

इस कार्यशाला की सफल समाप्ति उत्तर प्रदेश और भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत का संकेत देती है। भारत उन्नत विनिर्माण केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश को वैश्विक विनिर्माण परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार है, जो नवाचार, प्रौद्योगिकी और सतत आर्थिक विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

